



सबगुरु न्यूज़

(राष्ट्रीय द्विभाषीय पांक्षिक)

मो.9887907277 Email ID sabgurunews@gmail.com Website <https://www.sabguru.com>

सम्पादक - विजय सिंह

वर्ष 2

अंक 18

अजमेर, सोमवार 10 मार्च 2025

मूल्य 5 रुपए

पृष्ठ-4

12 साल बाद भारत बना आईसीसी चैपियंस ट्रॉफी का चैपियन

◆ रोमांचक मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया ◆ टीम इंडिया ने जीता चैपियंस ट्रॉफी का खिताब

दुबई। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद कप्तान रोहित शर्मा 76 श्रेयस अच्युत 48 और के एल राहुल, नाबाद 34 की बेहतरीन पारी की बदौलत भारत ने रविवार को फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराकर चैपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। भारत 12 साल बाद चैपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। 1252 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरूआत करते हुए पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी की। 19वें ओवर में मिचेल सैंटनर ने धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल 31 को आउटकर न्यूजीलैंड को पहली सफलता दिलाई। अगले ही ओवर में माइकल ब्रेसवेल ने विराट कोहली, एक को पगबाधा कर भारत को दूसरा झटका दिया। 27वें ओवर में रविन रविंद्र ने रोहित शर्मा को आउट कर भारत का बड़ा झटका दिया। रोहित शर्मा ने 83 गेंदों में सात चौके और तीन छक्के लगाते हुए 76 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। 39वें ओवर में



अजमेर के आसमान में झलका जीत का जश्न

टीम इंडिया की जीत के साथ ही अजमेर में क्रिकेट प्रेमियों ने जमकर आतिशबाजी की। आसमान रंग बिरंगी रोशनी से दमक उठा। गली मोहब्बों में लोगों ने सड़कों पर आकर जमकर पटाखे चलाए। एक दूसरे का मुँह भीता कराया। टीम इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाए।

मिचेल सैंटनर ने श्रेयस अच्युत को आउटकर न्यूजीलैंड को चौथी सफलता दिलाई। श्रेयस अच्युत ने 62 गेंदों में दो चौके और दो छक्के लगाते हुए 48 रन बनाये। इसके बाद अक्षर पटेल, 29 रन बनाकर आउट हो गये। भारत ने न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराकर चैपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। भारत ने 12

साल के बाद चैपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। के एल राहुल 34 और रविंद्र जडेजा नौ रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड की ओर से मिचेल सैंटनर और माइकल ब्रेसवेल ने दो दो विकेट लिये। रविन रविंद्र और काइल जेमीसन ने एक एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहले न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। बल्लेबाजी करने उत्तरी विल यंग और रविन रविंद्र की सलामी जोड़ी ने न्यूजीलैंड के अच्छी शुरूआत करते हुए पहले विकेट के लिए 58 रन जोड़े। आठवें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने विल यंग 15 को पगबाधा आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद 11वें ओवर में कुलदीप यादव ने रविन रविंद्र 37को आउट कर न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दिया। बल्लेबाजी करने उत्तरी विल यंग 18 रन बनाकर आउट हो गये। भारत ने न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराकर चैपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। भारत ने 12

गेंदों में तीन चौके लगाते हुये, 63 रनों की जूझार पारी खेली। सातवें विकेट के रूप में 49वें में कप्तान मिचेल सैंटनर, आठवें ओवर में बल्लेबाजी करने उत्तरी विल यंग 15 को पगबाधा आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद 11वें ओवर में कुलदीप यादव ने केन विलियमसन के साथ पारी संभालने का प्रयास किया।

13वें ओवर में कुलदीप यादव ने केन विलियमसन 16 को अपनी ही गेंद पर कैच

आउटकर पवेलियन भेज दिया। 24वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने टॉम लेथम 14 को पगबाधा आउट कर भारत के लिये चौथा विकेट झटका। ग्लेन मिलिप्स ने डेरिल मिचेल का बख्बाबी साथ निभाया। दोनों के बल्लेबाजों के बीच पांचवें विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी हुई। वरुण चक्रवर्ती ने 38वें ओवर में ग्लेन मिलिप्स, 34 वें ओवर में मोहम्मद शमी ने डेरिल मिचेल का बड़ी सफलता दिलाई। डेरिल मिचेल ने 101 गेंदों में तीन चौके लगाते हुये, 63 रनों की जूझार पारी खेली। सातवें विकेट के रूप में 49वें में कप्तान मिचेल सैंटनर, आठवें ओवर में बल्लेबाजी करने उत्तरी विल यंग 15 को पगबाधा आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद 11वें ओवर में कुलदीप यादव ने रविन रविंद्र 37को आउट कर न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दिया। बल्लेबाजी करने उत्तरी विल यंग 18 रन बनाकर आउट हो गये। भारत ने न्यूजीलैंड को चार विकेट पर 251 रन का स्कोर खड़ा किया। भारत की ओर वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने दो दो विकेट लिये। रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

कोचिंग सेंटर को कानूनी दायरे में लाने के लिए आएगा विधेयक

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की बैठक



जयपुर। राजस्थान सरकार ने दिव्यांगजन कल्याण कर्मचारी कल्याणनगर सुधार न्यास एवं विकास प्राधिकरणों में सुशासन और अक्षय ऊर्जा से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मन्त्रिमण्डल की बैठक में ये निर्णय किए गए। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द्र बैरवा एवं संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रदेश में संचालित कोचिंग केन्द्रों पर प्रभावी नियंत्रण करने और इनमें पढ़ रहे विद्यार्थियों को मानसिक संबल एवं सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दि राजस्थान कोचिंग सेंटर्स केंट्रों ले एंड रेगुलेशन बिल-2025 के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। यह विधेयक केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों राज्य की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं विभिन्न स्टेट कॉलेज के स्थानीय उद्योगों की जरूरतों के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस नीति में अनुभवी श्रमिकों के कौशल प्रमाणीकरण एवं री-स्ट्रिक्लिंग और अप-स्ट्रिक्लिंग कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाएगा ताकि श्रमिक बदलते औद्योगिक वातावरण में तालमेल विता सकें। पटेल ने कहा कि इस नीति के अन्तर्गत युवाओं को उद्योग की नई आवश्यकताओं के अनुसार उत्तर पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का आधुनिकीकरण कर विशेष कौशल केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इसी प्रकार श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड द्वारा पारम्परिक कारीगरों को बेहतर कौशल और व्यापक बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए काम किया जाएगा।

सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कॉर्ट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। अथॉरिटी के अधीन प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक जिला समिति का गठन किया जाएगा। पटेल ने बताया कि मन्त्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित राज्य कौशल नीति औद्योगिक क्षेत्रों की मांग के अनुरूप युवाओं को विशेष कौशलों में प्रशिक्षित कर वैश्विक प्रतिरिक्षण के लिए तैयार करेंगी और राज्य के औद्योगिक विकास में सहायता सिद्ध होंगी। इस नीति के माध्यम से आईटीआई को नए युग के उत्तम कौशल केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। आईटीआई में नए कोर्स एम्ड्यूल और उद्योगों के साथ ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी संभागीय मुख्यालयों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित कर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण कैरियर परामर्श एवं इंटर्नशिप और रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य कौशल नीति के अन्तर्गत ऑटोमेशन एवं एआईए मरीन लर्निंग एवं आईओटी स्टार्ट मैन्यूफैक्रिंग और साइबर सुरक्षा जैसे आधुनिक तकनीक वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर युवाओं को इंडरट्री 4.0 के लिए तैयार किया जाएगा। रथानीय औद्योगिक कलस्टरों के पास कौशल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। रिकरूट ट्रेन डेप्लॉय मॉडल के तहत रथानीय उद्योगों की जरूरतों के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस नीति में अनुभवी श्रमिकों के कौशल प्रमाणीकरण एवं री-स्ट्रिक्लिंग और अप-स्ट्रिक्लिंग कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाएगा ताकि श्रमिक बदलते औद्योगिक वातावरण में तालमेल विता सकें। पटेल ने कहा कि इस नीति के अन्तर्गत युवाओं को उद्योग की नई आवश्यकताओं के अनुसार उ

सम्पादकीय

आखिर कैसे रुकेगा निजी अस्पतालों में मरीजों का ‘शोषण’ जिम्मेदार कौन?

चिकित्सा पेशा या स्वास्थ्य व्यवसाय कोई सामान्य पेशा नहीं है बल्कि यह व्यक्तिगत जीवन और जनस्वास्थ्य से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें थोड़ी-सी भी लापरवाही किसी के जीवन पर भारी पड़ सकती है। वहाँए अपना या अपने परिवार का इलाज करवाने के चक्र में यदि कोई व्यक्ति या परिवार लूट-पिट जाए तो यह भी प्रशासनिक नजरिए से अनुचित है। और ऐसे ही जरूरतमंद लोगों के पक्ष में सरकार और समाजसेवी संस्थाओं दोनों को अवश्य खड़ा होना चाहिए। यहीं वजह है कि जनस्वास्थ्य से जुड़े चिकित्सा पेशा या स्वास्थ्य व्यवसाय को सिर्फ़ कारोबारी लाभ के नजरिए से नहीं देखा जा सकता है बल्कि यह एक सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व से जुड़ा हुआ विषय, पेशा है जिसे जनसेवा की भावना से किया जाए तो सरकार और संस्था दोनों को यश मिलेगा। भारतीय सभ्यता व संस्कृति तो शुरू से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया की पक्षधर रही है। लेकिन देश में लागू नई आर्थिक नीतियों से उपजी नैतिक व कानूनी महामारी के दौर में जीवन का हार क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। दुर्भाग्य है कि चिकित्सा पेशा भी इससे विद्यत नहीं है। चर्चा है कि महज आर्थिक लाभ के उद्देश्य से चिकित्सक महंगी जांच और अनावश्यक दवाइयाँ लिख रहे हैं। जानलेवा ऑपरेशन करने और अंगों के कारोबार तक से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार और न्यायिक जटिलताओं से ऐसे बहुत कम मामले हैं जो कोर्ट की दहलीज तक पहुंच पाते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राय सरकारों से यह कहना कि वे प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों के शोषणश् को रोकने के लिए उचित नीतिगत फैसला लें देर आयद दुरुस्त आयद जैसा है। जनहित के इस सवाल पर राय सरकारों को तुरंत एक्शन में आना चाहिए। दरअसल एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्राइवेट अस्पतालों और उनकी फर्मेंसी में एमआरपी से 'यादा कीमत वसूली जा रही है। लिहाजाए कोर्ट ने इन अस्पतालों पर खुद से प्रतिबंध लगाने से इनकार किया और कहा कि ये संविधान में राय सूची का विषय है इसलिए राय सरकारें ही इस पर व्यापक दृष्टिकोण से विचार कर सकती हैं। वही उचित गाइडलाइंस बना सकती हैं। इसमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा जिससे न तो मरीजों और उनके परिजनों का शोषण हो और न ही प्राइवेट अस्पतालों के कामकाज पर बेवजह प्रतिबंध लगे। बता दें कि यह जनहित याचिका सिद्धार्थ डालमिया, कानून के छात्रद्व्द ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि उनकी मां को पिछले साल कैंसर हुआ था और वह अब ठीक हो चुकी है। लेकिन उनके इलाज के दौरान प्राइवेट अस्पतालों में जबरन महंगी दवाएं खरीदनी पड़ीं। लिहाजाए इनकी गुहार है कि मरीजों और परिजनों को यह आजादी मिले कि वे अपनी पसंद की फर्मेंसी से दवाएं मेडिकल इक्लिप्मेंट आदि खरीद सकें। हालांकि ए केंद्र ने कोर्ट में कहा है कि मरीजों पर विशेष फर्मेंसी से दवाएं मेडिकल इक्लिप्मेंट लेने की बाध्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है। भले ही बढ़ती आबादी के कारण सरकार को प्राइवेट अस्पतालों की मदद लेनी पड़ी ए लेकिन इसमें मरीजों का शोषण नहीं होना चाहिए। हालांकि ए निजी हॉस्पिटल्स में जिस तरह से कैशलेस इलाज का प्रचलन बढ़ा है इस धंधे में बड़ी-बड़ी निजी कैशलेस चिकित्सा बीमा कम्पनियाँ सामने आयी हैं उन्होंने अस्पतालों के पैनल जारी किए हैं उससे एक संगठित लूट और इसी चक्र में मानव स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ बढ़ा है। निजी अस्पतालों में तो चुपके चुपके नई नई दवाइयों का परीक्षण तक मानव शरीर पर हो जाता और किसी को भनक तक नहीं लगती। कुछ निजी अस्पताल व उनके डॉक्टर तो रक्त और मानव अंगों के अवैध कारोबार तक में शामिल हैं। ऐसे आरोप अक्सर मीडिया में उछलते रहते हैं। वहाँए जब से केंद्र सरकार गरीबों को आयुष्मान भारत कार्ड बनाने लगी है और 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने लगी है तब से नए नए घोटालों और अनैतिक करतबों की बाढ़ आ चुकी है। इन सबके दृष्टिगत सरकार भले ही एहतियाती कार्रवाई करती आई है पर भी निजी चिकित्सा सेवा प्रदाताओं में इन नियमों का खोफनहीं है। क्योंकि अक्सर चिकित्सक हड्डाल या दवा कारोबारी हड्डाल की धमकियाँ देकर हेतु सिंडिकेट से जुड़े लोग सरकार और प्रशासन को ब्लैकमेल कर लेते हैं। लेकिन सवाल पिछे वही कि मानव स्वास्थ्य से खिलवाड़ कब तक।

महिलाओं का विकसित भारत, विकसित राजस्थान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान - भजनलाल शर्मा



जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं का विकसित भारत.विकसित राजस्थान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान बताते हुए कहा है कि वे राजनीतिए कलाए खेलए शिक्षाए स्वास्थ्यए सुरक्षा सहित हर भौर्चे पर अपने उत्कृष्ट कार्यों से देश और प्रदेश को गौरवान्वित कर रही हैं। शर्मा शनिवार को बिड़ला सभागार में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित राय स्तरीय महिला सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने मातृशक्ति का आङ्गन किया कि अंतिम पंक्ति पर खड़ी जरुरतमंद महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए मिलकर प्रयास करें और देश-प्रदेश को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि महिलाएं त्याग, करुणा, स्नेह, धैर्य सहनशीलता, संवेदनशीलता, सौम्यता, विनम्रता, वीरता, सहानुभूति जैसे अनेक गुणों की प्रतिमूर्ति होती हैं। यह दिन मातृशक्ति के योगदान को सम्मान देने का अवसर तथा हर क्षेत्र में महिलाओं की शानदार उपलब्धियों पर गर्व करने का दिन है। उन्होंने कहा कि हर बच्चे के लिए उसकी मां ही उसकी प्रथम गुरु होती है तथा व्यक्तिको सुशिक्षित एवं सभ्य बनाने में नारी का बहुत बड़ा योगदान होता है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में नारी को हमेशा सम्मान दिया गया है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर दिए जा रहे एक लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड की राशि को बढ़ाकर एक लाख 50 हजार रुपए करने की घोषणा की। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फैसलों से देश में महिलाएं सशक्त तथा आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसी कड़ी में आज के दिन प्रधानमंत्री के डिजिटल सोशल मीडिया अकाउंट की जिम्मेदारी भी नारी शक्ति को ही सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जहां घर-घर में शौचालय बनवाकर नारी शक्ति को उचित सम्मान दिया वहाँ उज्ज्वला योजना से हर घर तक रसोई गैस सिलेंडर पहुंचाया। हमारी सरकार भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आधी आबादी की उन्नति और प्रगति के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाया जिससे महिलाओं के लिए लोकसभा और राय विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार महिलाओं के कल्याण और हितों के लिए काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना के तहत तीन लाख से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। साथ ही ए मातृवंदन योजना से करीब पांच लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं तथा साथिन बहनों के मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 10 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों पर पौधारोपण जैसे कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हम सबके लिए गौरव की बात है कि देश और प्रदेश दोनों का बजट महिलाओं ने ही पेश किया है। हमारे इस बजट में भी महिला सशक्तीकरण की गति को तेज करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। संभागीय मुख्यालयों पर 50 बड़े के सरस्वती हाफ वे होम्स स्थापित 10 जिला मुख्यालयों पर बालिका देखभाल संस्थान नवगठित नगरीय निकायों में 500 पिंक टॉयलेट का निर्माण जैसे कदम बजट में उठाए गए हैं। इसी तरह बजट में हर ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय या

तृतीय शिक्षकों की पदोन्नति के लिए शीघ्र रास्ता निकलने की उम्मीद - मदन दिलावर

नागौर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि प्रदेश में तृतीय शिक्षकों की पदोन्नति के लिए आगामी दस पन्द्रह दिन में कोई रास्ता निकलने की उम्मीद है और इससे करीब 25 हजार शिक्षकों की पदोन्नति हो सकेगी और हम इस तरह एक साल में 50 हजार शिक्षकों की पदोन्नति करने में सफल रहेंगे। दिलावर रविवार को यहां मीडिया से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय पांच साल में शिक्षकों की पदोन्नति नहीं की गई और इससे कोई रिक्त पद नहीं भराए जिससे शिक्षकों की कमी रही। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने चाहा कि सभी प्रकार डीपीसी होनी चाहिए और जो प्राप्तता रखता है उनका प्रमोशन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने अभियान चलाकर 25 हजार शिक्षकों का प्रमोशन कर दिया है और तृतीय श्रेणी शिक्षकों का द्वितीय श्रेणी के लिए प्रमोशन किया गया है। अभी बाकी है अदालत में कुछ मामला है हम अदालत में भी अपनी बात अच्छी तरह रख रहे हैं और शायद 10.15 दिन में कोई रास्ता निकल आयेगा। उन्होंने कहा कि इससे करीब 25 हजार प्रमोशन होंगे और इस तरह एक साल में 50 हजार शिक्षकों के प्रमोशन करने में हम सफल रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा शिक्षकों के भर्ती निकालकर 12 हजार शिक्षकों के पद भरे हैं और मुख्यमंत्री की चार लाख लोगों को सरकारी नौकरी की घोषणा के तहत भी शिक्षकों की भर्ती होगी और इसके बाद शिक्षकों के लगभग



सभी रिक्त पद भर जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो अध्यापक अच्छी पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं उनके खिलाफ उनका अन्य जगह स्थानांतरण आदि की कार्यवाही किए जाने का कहने के बाद शिक्षक विद्यालयों में बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं और शायद अब यह नौबत नहीं आएगी कि अध्यापक के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार के नियम के अनुसार जो विद्यार्थी 80 में से 13 अंक लाने वाला पास हो जाएगा; 20 अंक स्कूल की तरफ से मिलाने परद्ध लेकिन अब हमने यह कर दिया कि इतने अंक लाने पर बच्चा तो पास हो जाएगा लेकिन बच्चे के 80 में से 40 अंक नहीं आने पर अध्यापक फेल हो जाएगा। दिलावर ने कहा कि ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जगह स्थानांतरण विकास के बाद विद्या पढ़ा रहे हैं और शायद कि अध्यापक के पड़े। उन्होंने कहा नियम बोर्ड की परीक्षा में एक बड़ा कम आने पर परीक्षा रिटेस्टिंग की व्यवहार कई बार नम्बर बढ़ के मन रहता है। मुताबिक नम्बर नियैकिंग भी करा रखा रखियैकिंग की व्यवहार पायलट प्रोजेक्ट के और इसके अच्छे सभी विषयों में इसे

कार्काराई की जाएगी और उहें अन्यथा नांतरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाद विद्यालयों में शिक्षक अच्छे हैं और शायद अब नौबत नहीं आएंगी ध्यापक के खिलाफ एकशन लेने होने कहा कि जिन विद्यार्थियों के परीक्षा में उनके अनुमान से अंक बाने पर परीक्षा में आए अंकों की लिंग की व्यवस्था हैं और इसके तहत बर नम्बर बढ़ भी जाते हैं लेकिन बच्चे रहता हैं कि उसकी मेहनत के क्रम नम्बर नहीं मिले तो अब वे भी करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि ग की व्यवस्था गणित विषय से जुड़ प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर रहे हैं सके अच्छे परिणाम आने पर शोषण विषयों में इसे लागू किया जाएगा।

अमरीका में पहली बार हत्यारे
को गोली से उड़ाकर मृत्युदंड

वाशिंगटन। अमेरीका में हत्या के एक दोषी को शुक्रवार को फायरिंग दरते ने मृत्युदंड दिया। दक्षिण कैरोलिना के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि 15 वर्षों में यह अपनी तरह का पहली ऐसी ही है।

दक्षिण कैरोलिना सुधार विभाग ने एक बयान में कहा कि ब्रैड कीथ सिगमन की मौत की सजा शुक्रवार रात को एस्सी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और राज्य के कानून के अनुसार पूरी की गई। शाम 6.05 बजे तीन लोगों की फयरिंग स्क्वाड ने गोली मारकर उसे मौत की सजा दी। शाम 6.08 बजे एक चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद, ब्यावर में बंद के दौरान पसरा सन्नाटा

◆ काले कोट वालों के आक्रोश के सामने बौनी नजर आई खाकी ◆ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेटिया की मौत से वकील आक्रोशित



अजमेर। तीर्थनगरी पुष्कर के वरिष्ठ वकील पुरुषोत्तम जाखेटिया के हमले में घायल होने के बाद उपचार के दौरान मौत से समूचे अधिवक्ता वर्ग में आक्रोश व्याप्त हो गया। शनिवार को अजमेर शहर ब्यावर, पुष्कर, नसीराबाद समेत कई कस्बों में बंद रखा गया। अजमेर शहर में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। मदार गेट, केसरांजन, दरगाह बाजार, वैशाली नगर, आदर्श नगर, रस्टेशन रोड पर दिनभर सन्नाटा पसरा रहा। व्यापारिक महासंघ का समर्थन मिलने से अधिकांश कारोबारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे इसके बावजूद कुछ जगह वकीलों और दुकानदारों तथा पुलिस के बीच तकरार भी हुई। दरगाह बाजार में दुकान खुली रहने पर बंद समर्थकों ने हंगामा कर दिया। वकील दिनभर समूहों में निकलकर बंद को सफल बनाने में जुटे रहे। इस दौरान पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी मय जासे के वकीलों को समझाइश करते नजर आए।

बंद को सफल बनाने में जुटे वकीलों ने डंडे लेकर शहर में जुलूस निकाले तथा जो भी दुकान खुली भिली उसमें तोड़फोड़ की। पंचशील स्थित सिटी स्कायर मॉल में एक ब्रॉडेड शोरूम को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसी तरह वैशाली नगर में एक सैलून में काम करने वाले की बुरी तरह पिटाई कर डाली। चौपाटी के सामने तो पुलिस और वकीलों के बीच हाथपाई की नींबत आ गई। हालात नाजुक होते देख कलेक्टर लोकबंधु तथा पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा मौके पर पहुंचे और जैसे तैसे पुलिस और वकीलों के बीच विवाद बढ़ने से टाला। दीगर बात यह है कि इस बार बंद के आहवान में महिला वकील भी अपने साथियों के साथ धूमकर प्रदर्शन करते हुए नारे लगाती रहीं।

अब आगे क्या?

महापङ्क्ति की तैयारी

बंद के बाद अपराह्न बाद सेशन कोर्ट के समक्ष बने अस्थाई मंच से जिला बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत व सचिव दीपक गुप्ता व उपाध्यक्ष गगन वर्मा ने वकीलों के आंदोलन में सहयोगी रहने वाले व्यापारी, टेम्पो, टैक्सी, ई रिक्शा, सिटी बस चालक व संचालकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वकीलों की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

जिला बार प्रदेश के सभी अधिवक्ता संगठनों को पत्र भेजकर इस घटना की सूचना देंगे और अजमेर में वकीलों की महापङ्क्ति आयोजित करने के लिए रायशमारी कर सभी की सहमति से उसे मूर्तरूप दिया जाएगा।

मृतक अधिवक्ता जाखेटिया का अंतिम संस्कार



पुष्कर के ग्राम नेडलिया निवासी अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेटिया का शव करीब 3 दिन जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय की मार्चरी में ही रखा रहा। शव का पोस्टमार्टम तक नहीं हो सका। जिला बार एसोसिएशन व परिजनों की मांग पूरी होने पर दाह संस्कार किए जाने की जिद पर आंदोलनकारी वकील अडे रहे। आखिरकार शनिवार देर शाम मृतक अधिवक्ता के परिजनों को 1 करोड़ रुपए

मुआवजा देने मृतक के एक परिजन को सरकारी नौकरी आरोपियों के खिलाफ जल्द चार्जशीट पेश करने तथा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने समेत 5 सूत्री मांग पर सर्किट हाउस में 8 मार्च को देर शाम विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत के बीच वार्ता के बाद दिवंगत वकील जाखेटिया के शव का दाह संस्कार करने पर सहमति बनी। पुष्कर स्थित छोटी बस्ती पुष्कर मोक्ष धाम में रविवार शाम शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

दो मुख्य आरोपियों समेत 8 पुलिस रिमांड पर

वरिष्ठ धरक्ता पुरुषोत्तम जाखेटिया की हत्या के सभी 11 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इनमें से तीन आरोपी जेल में हैं तथा दो मुख्य आरोपी समेत सभी 8 आरोपी पुलिस रिमांड पर रहे हैं। थाना प्रभारी घनश्याम सिंह राठोड ने बताया कि वकील जाखेटिया पर हमला करने के दो मुख्य आरोपी शक्ति सिंह रावत व हेमराज मेघवाल समेत सभी 11 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। इनमें से पहले दिन पकड़े गए 3 आरोपियों को जेल भिजवा दिया जबकि 8 आरोपी रिमांड पर हैं। अधिवक्ता की मौत के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर नए सिरे से जांच की जा रही है।

पुष्कर में वकीलों ने निकाली रैली

पुष्कर में अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेटिया पर हुए हमले के बाद उनके निधन से नगरवासियों व वकील समुदाय में भारी आक्रोश व्याप्त है। बार एसोसिएशन के आहवान पर शनिवार को बंद के आयोजन को व्यापारी वर्ग ए आमजन और विभिन्न संगठनों का व्यापक समर्थन मिला। मेडिकल स्टोर संचालकों ने भी सुबह दो घंटे स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। सुबह कोट परिसर में वकील जमा हुए तथा बार अध्यक्ष कुलदीप पाराशर के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से बंद को सफल बनाने के लिए मुख्य बाजार से रैली भी निकाली। दिनभर बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। बंद के कारण बाहर से आने वाले तीर्थ यात्रियों तथा पर्यटकों को असुविधा का सामना करना पड़ा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से डटा रहा।

दिवंगत अधिवक्ता के परिजनों को सौंपी आर्थिक सहायता राशि



अजमेर। पुष्कर के दिवंगत अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेटिया मृत्यु प्रकरण में प्रशासन व वकीलों में सहमति के बाद रविवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत पुष्कर पहुंचे तथा शोक संतुष्ट परिवार को आर्थिक सहायता राशि सौंपी। जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को शराब का ठेका हटाने व वकीलों की अन्य मांगों पर भी शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए। पुष्कर के अधिवक्ता जाखेटिया की मृत्यु प्रकरण में रविवार को सहमति बनी। अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा अध्यक्ष ए अन्य जनप्रतिनिधि व प्रशासन में वार्ता की। दोपहर बाद विधानसभा अध्यक्ष देवनानी, केन्द्रीय मंत्री चौधरी, केबिनेट मंत्री रावत व अन्य जनप्रतिनिधि पुष्कर पहुंचे। उन्होंने पुष्कर में जाखेटिया के अंतिम संस्कार में श्रद्धांजलि अर्पित की तथा जाखेटिया के निवास पर पहुंच कर परिवार को आर्थिक सहायता राशि सौंपी। विधानसभा अध्यक्ष व मंत्रीगण ने प्रशासन को निर्देश दिए कि शराब के ठेके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही जांच सहित अन्य मांगों पर तत्काल कार्यवाही शुरू की जाए। इस अवसर पर पूर्व विधायक देवी शंकर भूतः सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपरिस्थित रहे।

सीएम से मिले पुष्कर विधायक एवं मंत्री रावत



पुष्कर के वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेटिया की हत्या के मामले में स्थानीय विधायक एवं जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात त्वरित कार्रवाई की अपील की। मंत्री रावत ने आग्रह किया कि आरोपियों को जल्द से जल्द कठोर सजा दिलाकर जाखेटिया परिवार को न्याय दिलाया जाए। रावत ने बताया कि 2 मार्च को दिवंगत जाखेटिया के साथ कुछ युवकों ने लैजे बजाने से रोकने के कारण मारपीट की थी जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई थी। लंबी चिकित्सा प्रक्रिया के बाद जाखेटिया का निधन हो गया। इस घातक घटना को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने मुख्यमंत्री से तत्काल कार्रवाई की अपील की।

रावत ने कहा कि यह घटना हम सभी के लिए भी बहुत कष्टकारी है। इसलिए सरकार को इस मामले में गंभीरता से विचार करते हुए आरोपी युवकों को जल्द से जल्द कठोर सजा दिलाएं ताकि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। रावत ने कहा कि इस प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया को तेज गति प्रदान की जाए एं पीड़ित परिवार की मांगों पर शीघ्र संवेदना पूर्वक निर्णय कर अधिकाधिक सहायता प्रदान कराई जाए।